

उत्तर प्रदेश: सेमीकंडक्टर वनिरिमाण इकाइयों के लिये अनुकूल

चर्चा में क्यों?

एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रस्तावित **सेमीकंडक्टर नीति 2024** पर आधारित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।

मुख्य बंदि:

- मुख्यमंत्री ने कहा कि **सेमीकंडक्टर वनिरिमाण उद्योगों में उन्नत के साथ-साथ उच्च दक्षता वाले उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिकित्सा संबंधित उपकरणों में** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार** को भी बढ़ावा देता है।
- यह **राज्य की आर्थिक वृद्धि** और नवाचार में योगदान देगा तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए पर्याप्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।
- युवाओं को सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये** मुख्यमंत्री ने राज्य के दो IIT सहित तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
 - सेमीकंडक्टर उद्योगों में CM इंटरनशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिये दो वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था** की जानी चाहिये।
- सेमीकंडक्टर चपि क्षेत्र** ने पछिले दो वर्षों में **500 बलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश करने की योजना** की घोषणा की है।
 - सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये, **भारत सरकार ने 10 बलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन परियोजना प्रदान करने का निर्णय लिया है।**
- सीएम का सुझाव है** कि नीति में वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिये वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण के प्रावधान शामिल होने चाहिये।
 - ऐसा करने वाला **उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य** होगा।
- नई नीति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी के अलावा **अतिरिक्त पूंजी निवेश** भी शामिल होना चाहिये।
 - भूमि की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट** का भी प्रावधान होना चाहिये।
- नीति में** विद्युत शुल्क में छूट, ड्यूल पावर ग्रिडि नेटवर्क ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग शुल्क, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, पेटेंट, जल आपूर्ति, पावर बैंकिंग, अनुसंधान और विकास सहायता हेतु प्रावधान किये जाने चाहिये।